भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 135
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

टियर-III शहरों में कौशल भारत केन्द्र

135. श्रीमती मालविका देवी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के त्रिस्तरीय शहरों में कौशल भारत केन्द्र खोलने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले स्वतंत्र व्यवसाय मालिकों को पच्चीस वर्ष से कम आयु के स्वतंत्र व्यवसाय मालिकों को सुविधा प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने में सहायता करने के लिए कोई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को अपनाने संबंधी बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार से उद्योग 4.0 को सहायता प्रदान करेगा?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल विकास केंद्र खोलना मांग आधारित है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य और उद्योग के लिए तैयार कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 10,006 प्रशिक्षण केंद्र, जेएसएस के अंतर्गत 290 केंद्र, सीटीएस के अंतर्गत 15,034 आईटीआई और एनएपीएस के अंतर्गत 46,764 प्रतिष्ठान हैं।

(ख) सरकार ने देश भर में रोजगार अथवा सूक्ष्म उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई विस्तृत पहल इस प्रकार हैं:

(i) भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन देने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घावधि स्कीमें/कार्यक्रम/नीतियाँ शामिल हैं।

(ii) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) 1 अक्तूबर, 2020 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए रोजगार के

नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना था। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी।

(iii) सरकार 01 जून, 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि स्कीम) को कार्यान्वित कर रही है, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को अपने व्यवसायों को पुनः शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके, जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।

(iv) स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की गई। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 10 लाख रुपए तक का बिना किसी जमानत के ऋण दिया जाता है, ताकि वे अपनी व्यावसायिक कायाकलापों को स्थापित या विस्तारित कर सकें।

(v) सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है।

(vi) पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों अर्थात् सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद अवसंरचना द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है, जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के बड़े अवसर पैदा होते हैं।

(vii) भारत सरकार रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) और दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी स्कीमों पर पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है।

(viii) इन पहलों के अलावा, सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सभी के लिए आवास आदि भी रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में उन्मुख हैं।

ग. स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) एक मोबाइल-फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता परिदृश्य को समन्वित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कौशल वृद्धि के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच प्रदान करना है, जो उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, जॉब के अवसर और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है। एसआईडीएच कौशल अवसरों और एकीकृत मंच का एक डिजिटल विस्तार है जिसमें हितधारकों के बीच डिजिटल जॉब एक्सचेंज है।

इस मंच को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एकीकृत करके, यह मंच कौशल विकास पहलों के लिए एक एकीकृत और केंद्रीकृत केंद्र बनाने का प्रयास करता है।

एसआईडीएच सरकार के दो सबसे महत्वपूर्ण घटकों- स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के संगम पर स्थित है। मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण पर निर्मित, एसआईडीएच कौशल विकास के लिए नागरिकों की विविध आवश्यकताओं अर्थात वरीयताओं और आकांक्षाओं के आधार पर पाठ्यक्रम, स्कीमें, शिक्षुता और जॉब के अवसरों की खोज, डिजिटल कौशल के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, पोर्टेबल सत्यापित क्रेडेंशियल और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए बहुभाषी, आदि

को पूरा करता है। इसका उद्देश्य भारत के कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता परिदृश्य के लिए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की सेवा करना है। यह मंच डीपीआई के निर्माण के लिए जी20 परिणाम दस्तावेज़ में व्यक्त दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एसआईडीएच अपने डिजिटल लर्निंग भागीदारों द्वारा प्रदान किए गए बिग डेटा, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स आदि पर भविष्य के पाठ्यक्रम प्रदान करके उद्योग 4.0 का समर्थन करता है। डिजिटल तकनीक और कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एसआईडीएच अंततः उद्योग 4.0 के लिए आवश्यक अधिक कुशल और गतिशील कार्यबल का मार्ग प्रशस्त करता है। उद्योग 4.0 पाठ्यक्रम जैसे कि एडवांस्ड कृत्रिम मेधा (एआई) के साथ पायथन, कृत्रिम मेधा फाउंडेशन, जेनरेटिव एआई, सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल बनाना, डेटा एनालिटिक्स एसेंशियल, रिलेशनल डेटा वेयरहाउस में डेटा का विश्लेषण, साइबर सुरक्षा एसेंशियल, डेटा साइंस का परिचय, किसान ड्रोन ऑपरेटर, ईवी सर्विस तकनीशियन, बायो-वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही अन्य प्रमाणन पाठ्यक्रम, मंच पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

*****